कर्मचारियों के लिए अपेक्षित स्थान के अलावा स्थान उपलब्ध हो।

(ख) देहरादून, चारबाग/लखनऊ में चल टिकट परीक्षक, डिब्बा परिचर तथा कंडक्टर मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के ड्राइवरों के साथ नहीं ठहरते हैं।

(ग) जी हां।

(घ) उपलब्ध संसाधनों के भीतर रनिंग कक्ष सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है ताकि ड्राइवर पर्याप्त विश्राम कर सकें।

Electric Trains For the Capital

8086. SHRI M. RAMGOPAL REDDY. Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is fact that Government propose to introduce sixty new electric trains round the Capital by the middle of this year.

(b) if so, whether the electric train service will be on the pattern of Bombay and Calcutta ; and

(c) what are the details in this regard ?

THE DEPUTY INISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN : (a) and Yes. (b)

(c) E.M.U. Services when introduced on the Ring Railway would serve all the existing stations. One additional crossing station is being provided at Pragati Maidan for serving the Trade Fair Complex. In all about 80 services shall be running when fully energised. During the morning and evening peak period it would provide 15 minute service in peak flow direction and 30 minutes service in non-peak flow direction. Besides this skelton services will also run from Shakurbasti to Delhi and Delhi to Tughlakabad and vice versa.

बसई, दारापुर से दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों को बसें चलाने संबंधी मांग

8087. श्री संजीव कुमार : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि रेजिडेंस वेल्फेयर एसोसियेशन, सुदर्शन पार्क ने बहुत से अभ्यावेदनों में बसई दारापुर से दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों को बस चलाने के लिए मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो वहां से अब तक कोई बस न चलाने के क्या कारण हैं ;

(ग) बसई दारापुर से कब तक बसें चलाई जायेंगी ; और

(घ) इस विलम्ब के क्या कारण हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) बसई-दारापुर से बस सेवा चलाना संभव नहीं है, क्योंकि कालोनी के पहुंचमार्ग, जो तंग पुल के उपर से गुजरते हैं, भारी गाड़ियों के लिए उपयुक्त नहीं है। कालोनी के निवासी कीर्तिनगर बस स्टाप के निकट बहुत सी बसों का लाभ उठा सकते हैं।

Public Undertakings Under Ministry Of Railways

8088. SHRI BHUKHABHAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the total number of Public Sector Undertakings Boards/Committees/Councils, etc. under the administrative control of his Ministry and the constitution of their Boards along with their tenure ;

(b) the date from which these Boards/Committees/Councils, etc. were constituted and when their present term is expiring ;

(c) details of SC/ST representatives appointed on Boards/Committees/Councils, etc. to watch the interest of SC and ST employees ; and

(d) in case no representation has been given, what steps are contemplated to implement Government policy of reservation for SC and ST on Board/Committees/Councils etc. ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways and in the Department of Parliamentary Affairs

(SHRI MALLIKARJUN) : (a) to (d) There are two Public Sector Undertakings under Ministry of Railways, namely, Rail India Technical & Economic Services Ltd. (RITES) and Indian Railway Construction Co. Ltd. (IRCON). These Undertakings came into exsitence in 1974 and 1976 respectively. The Board of Directors of RITES includes one Chairman (part-time), one Managing Director, one Director Technical, one Director Finance in addition to 4 ex-officio part time Directors from Ministry of Railways and other Ministries.

The Board of Directors of IRCON includes one Chairman (part-time), one General Manager and part time Director, in addition to 4 ex-officio Directors from Ministry of Railways. There is no tenure for the Boards of Directors of these Government undertakings.

A High Power Committee known as Railway Reforms Committee is also functioning on the Railways. This Committee was constituted on 12-5-1981. This Committee includes one Chairman and 6 members. The tenure of this Committee is 2 years.

There is no Member belonging on SC ST on the Boards of Directors of the above companies or on the above Committee. As for the Companies are concerned majority of the Directors occupy the position in ex-officio capacity. As for as Railway Reforms Committee is concerned, persons with expertise in specific spheres related to Committee functions have been nominated as Members on this Committee by the Government. The question of specific representations of SC or ST representatives on these Companies or on the Railway Reforms Committee, therefore, does not arise.

पश्चिम रेलवे को बड़ी और छोटी लाइन के कोचों की सप्लाई

8089. श्री मोतीभाई आर० चौधरी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे ने पिछले तीन वर्षों में बड़ी लाइन और छोटी लाइन के कितने कोचों और वेगनों की मांग की है और कितने दिए गए ; और

(ख) उनकी मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है और कब तक ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : पश्चिम रेलवे सहित अलग-अलग रेलों द्वारा सवारी तथा माल डिब्बों की मांग प्रस्तुत नहीं की जाती है। समूची भारतीय रेल प्रणाली की यातायात संबंधी समग्र आवश्यकता के लिए वार्षिक चल स्टाक कार्यक्रम के जरिये सवारी तथा माल डिब्बों का संयुक्त प्रावधान किया जाता है जो धन की उपलब्धता, उत्पादन क्षमता की सीमाओं तथा अन्य उत्पादन संबंधी दबाओं पर निर्भर करता है।

प्रत्येक रेलवे को सवारी तथा माल डिब्बों का आवंटन प्रत्येक रेलवे पर ऐसे गतायु स्टाफ, जिन्हें नाकारा करना और बदलना जरूरी होता है, विभिन्न रेलों पर आवधिक ओवरहालिंग आदि के लिए उपलब्ध अनुरक्षण क्षमता तथा यातायात की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम रेलवे को आवंटित किये गए सवारी तथा माल डिब्बों की संख्या नीचे दी गयी है :—

वर्ष	सवारी डिब्बों की संख्या	
	बड़ी लाइन	मीटर लाइन
1978—79	49	73
1979—80	101	17
1980—81	72	17

	माल डिब्बों की संख्या (चौपहियों के हिसाब से)	
	बड़ी लाइन	मीटर लाइन
	795	481
	502	476
	535	105